सरकारी डिस्पेंसरी की कमी

दुनु रॉय

1857 के ग़दर के तुरन्त बाद का ज़माना था, प्रिसिला विंटर 16 साल की उम्र में कलकत्ता पहुंची। उसे विलायत से भारतीय महिलाओं में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा गया था। परन्तु कलकत्ता की महिलाओं को घर की दहलीज़ से निकलने का मौका बस उस समय मिलता था जब वे घाट पर पूजा करने जाती थीं। इसलिए जब पांच साल बाद प्रिसिला की शादी हुई और वह अपने पति के साथ दिल्ली आई तो उसने यमुना घाट पर दवाई बांटने का काम आरम्भ किया। 1864 में जब दिल्ली में हैजा फैला तब देसी महिलाओं पर उसका असर देखकर प्रिसिला की आत्मा कांप उठी और वह विलायत लौट गयी।

विलायत में चैन से रहने की जगह प्रिसिला केवल महिलाओं के लिए डिस्पेंसरी खोलने के लिए पैसा जुटाने में लग गयी। 1867 में दिल्ली लौटकर उसने दिल्ली महिला मेडिकल मिशन की स्थापना की और चांदनी चौक में महिलाओं के लिए पहली डिस्पेंसरी खोली। धीरे-धीरे मिशन बढ़ता गया। 1875 में नर्सों के प्रशिक्षण का काम प्रारम्भ हुआ; 1881 में प्रिसिला का देहांत हो गया लेकिन फिर भी करनाल में एक शाखा खोली गयी; और 1885 में, प्रिसिला विंटर की याद में, दिल्ली में महिलाओं और बच्चों के लिए खैराती अस्पताल बनाने का सपना पूरा हुआ— जिसे हम आज सेंट स्टीफ़न अस्पताल के नाम से पहचानते हैं। 1906 में सेंट स्टीफ़न अस्पताल का तीस हज़ारी के पास स्थानांतरण हो गया।

आज उसी सेंट स्टीफ़न अस्पताल का हाल कैसे बदल गया है उसका अंदाज़ा लगाने के लिए 22 वर्षीय सुमन की कहानी सुनिए। नवम्बर 2014 में उसका पति बीमार सुमन को अस्पताल लेकर आया। जांच करने पर पता चला कि सुमन के मस्तिष्क में ट्यूमर (रसोली) है। ऑपरेशन और इलाज करने में 22 दिन लगे लेकिन सुमन के पति को अस्पताल में पांच लाख जमा करने के बाद ही छुटकारा मिला। एक शताब्दी में प्रिसिला के मुफ़्त चिकित्सा प्रदान करने के सपने को आज की बाज़ारी ताक़तों ने पूरी तरह से हज़म कर लिया है। उन्हीं ताक़तों ने सरकारी चिकित्सालयों को भी पंगु करने का काम किया है ताकि निजी अस्पतालों को कमाने के खुली छूट मिल जाए।

2007 से पहले दिल्ली में 56 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पी.एच.सी.) थे। फिर उनको बंद करके 2011 तक 1019 सरकारी डिस्पेंसरी खोली गईं जबकि महायोजना के मानकों के मुताबिक उस वक़्त 1675 डिस्पेंसरी होनी चाहिए थीं। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली के 2011 तक की महायोजना के मुताबिक 7500 की आबादी पर एक डिस्पेंसरी का प्रावधान था। उसके बाद जब 2021 तक की महायोजना का पहला प्रस्ताव आया तो उसमें इस प्रावधान को शामिल नहीं किया गया। लोगों के दवाब के चलते इस प्रावधान को दोबारा वापस तो लाया गया परन्तु मानक को बदल कर इसमें 10000 लोगों की आबादी पर एक डिस्पेंसरी खोलने का प्रावधान किया गया। पूर्व मानक के अनुसार आज की तारीख में 2433 डिस्पेंसरी होनी चाहिए थीं।

2001 में जनवादी महिला समिति द्वारा दिल्ली की बस्तियों में 5000 महिलाओं के साथ किए सर्वेक्षण में पाया गया था की 17 प्रतिशत औरतों को पेट की बीमारी थी, 6 प्रतिशत मलेरिया से ग्रस्त थीं, और 3 प्रतिशत को हैजा हो गया था। तीन चौथाई महिलाएं प्रति महीने औसतन 600 रुपये निजी डॉक्टरों पर खर्च कर रही थीं। फिर भी केवल 28 प्रतिशत महिलाएं (लगभग एक-चौथाई) ही सरकारी डिस्पेंसरी या अस्पताल में जाने को तैयार थीं क्योंकि सरकारी व्यवस्था काफ़ी लचर थी। दिल्ली सरकार की आमदनी में से इस समय मात्र 0.6 प्रतिशत स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च हो रहा है—

यानी रुपये में एक पैसा भी नहीं, जबकि एक ग़रीब परिवार एक रुपये में 20 पैसे अपने स्वास्थ्य खर्च कर रहा है।

जब तक स्वास्थ्य सेवाओं का यही हाल रहेगा और दिल्ली की महिलाओं के विभिन्न रोगों और परेशानियों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक एक स्वस्थ आबादी भी पैदा नहीं हो सकती। आंकड़ों के मुताबिक पूरी दिल्ली में 1000 में से 40 बच्चों की मृत्यु एक साल के अंदर हो जाती है जबकि ग़रीब बस्तियों में यह दर बढ़कर 54 हो जाती है। 75 प्रतिशत बच्चों को पेचिश है, 63 प्रतिशत कुपोषित हैं, 35 प्रतिशत ठिगने हैं, और 65 प्रतिशत को मां का दूध नसीब नहीं होता है। प्रति वर्ष मात्र 20 महिलाओं को ही जननी सुरक्षा योजना का लाभ मिल पाता है। हमारे नीति-निर्धारकों के बाज़ारू नज़रिये ने प्रिसिला के ही नहीं बल्कि दिल्ली की तमाम महिलाओं के सपनों को खोखला कर दिया है।

दुनु रॉय, *हैज़र्ड सेंटर के निदेशक हैं।*